स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस)

सन्दर्भ:

- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) 945 करोड़ रुपये की स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (Startup India Seed Fund Scheme - SISFS) का जमीनी स्तर पर प्रभाव देखने के लिए तीसरे पक्ष का आकलन कर रहा है।

मुख्य विशेषताएं:

- स्टार्ट अपके व्यापार चक्र के विभिन्न चरणों में पूंजी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी।
- इसके तहत सरकार ने फंड ऑफ फंड्स और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजनाओं को लागू किया है।

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस)

- 945 करोड़रुपये के कोष के साथस्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS) 1 अप्रैल 2021 से लागू हुई।
- इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा लॉन्च किया गया था।
- **उद्देश्य:**स्टार्टअप्स को अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, प्रोडक्ट परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- **समय अवधि:** इसे 2021-22 से शुरू होकर 4
- ईएसी योजना के तहत निधियों के लिए इनक्यूबेटरों का मूल्यांकन और चयन करता है।
- इसके बाद ये इनक्यूबेटर योजना दिशानिर्देशों में उल्लिखित कुछ मापदंडों के आधार पर स्टार्टअप का चयन करते हैं।

महत्व :

- भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बीज और 'अवधारणा के सबूत' विकास चरण में पूंजी की अपर्याप्तता से ग्रस्त है।
- यह इन स्टार्टअप्स को एक ऐसे स्तर तक आगे बढ़ने में सक्षम करेगा जहां वे निवेशकों या उद्यम पूंजीपतियों से निवेश जुटाने में सक्षम होने के साथ ही वाणिज्यिक बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
- यह टियर 2 और 3 क्षेत्रों में एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद करेगा, क्योंकि भारत के छोटे शहरों को अक्सर उचित धन उपलब्ध नहीं कराया जाता है।\

साल की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है।

ईएसी :

- उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) का गठन किया गया है।
- यह स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के समग्र निष्पादन और निगरानी के लिए कार्य करेगा।

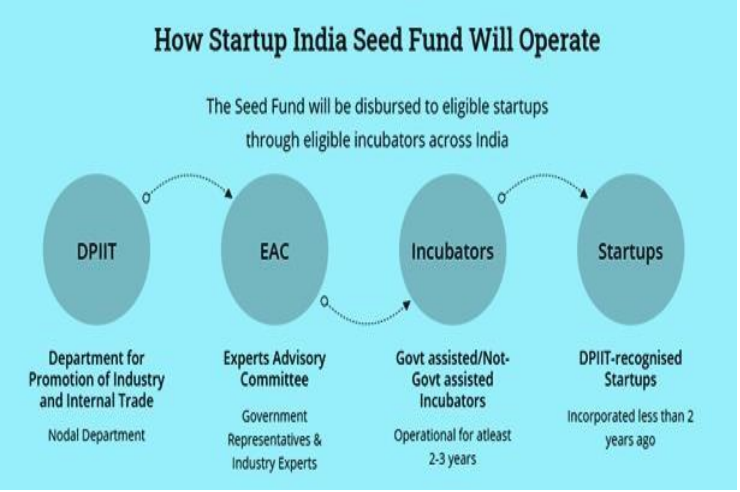

बीस सूत्री कार्यक्रम

सन्दर्भ:

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत सरकार ने बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत 14 में से छह मापदंडों में 90% से अधिक का लक्ष्य पूरा किया है।

मुख्य विशेषताएं:

- मंत्रालयकेअनुसार, अप्रैल-दिसंबर 2022 की अवधि में, 14 में से तीन मापदंडों में प्रदर्शन "खराब" या 80% लक्ष्य से नीचे था।
- इनमें वृक्षारोपण (सार्वजनिक और वन भूमि) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत सड़कों का निर्माण शामिल है।

बीस सूत्री कार्यक्रम:

- बीससूत्री कार्यक्रम की शुरूआत 1975 में की गई थी और बाद में 1982 और फिर 1986 में इसका पुनर्गठन किया गया।
- नई नीतियों और कार्यक्रमों की शुरूआत के साथ 2006 में इसे अंतत: पुनर्गठित किया गया जो वर्तमान में संचालित है।
- केंद्र में कार्यक्रम की निगरानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सौंपी गई है।
- यह ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकारी कार्यक्रमों का एक पैकेज है।
- इस कार्यक्रम में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कई योजनाएं शामिल हैं।
- ट्वेंटी पॉइंट प्रोग्राम (टीपीपी) 2006 के तहत कार्यक्रम और योजनाएं राष्ट्रीय सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों और सार्क सोशल चार्टर में निहित प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं।

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

04 मई 2023

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक

सन्दर्भ:

- ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट फ्रीडम

  इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग 180 देशों में से 161 हो गई है।

मुख्य विशेषताएं:

- इसकी तुलना में, पाकिस्तान ने मीडिया स्वतंत्रता के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है क्योंकि इसे 150वें स्थान पर रखा गया था, जो की पिछले वर्ष 157वीं रैंक पर था।
- भारत 2022 में 150वें स्थान पर था।
- श्रीलंका ने भी सूचकांक में महत्वपूर्ण सुधार किया, जो 2022 में 146वें स्थान की तुलना में इस वर्ष 135वें स्थान पर रहा।
- नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क ने प्रेस स्वतंत्रता में शीर्ष तीन स्थानों पर कब्जा किया, जबकि वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया नीचे के तीन स्थानों पर रहे।

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) के बारे में:

- यह हर साल प्रेस स्वतंत्रता की वैश्विक रैंकिंग जारी करता है।
- आरएसएफ एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ है जिसका स्वघोषित उद्देश्य मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना है।
- इसका मुख्यालय पेरिस में है।
- इसे संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार का दर्जा प्राप्त है।
- विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का उद्देश्य, "पिछले कैलेंडर वर्ष में 180 देशों और क्षेत्रों में पत्रकारों और मीडिया द्वारा प्राप्त प्रेस स्वतंत्रता के स्तर की तुलना करना है"।
- परिभाषा: आरएसएफ प्रेस की स्वतंत्रता को "राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी और सामाजिक हस्तक्षेप से स्वतंत्र और उनके शारीरिक और खतरे के अभाव में जनहित में समाचारों का चयन, निर्माण और प्रसार करने के लिए व्यक्तियों और सामूहिक रूप से पत्रकारों की क्षमता" के रूप में परिभाषित करता है।

विश्व बैंक

सन्दर्भ:

- भारतीय मूल के अजय बंगा जल्द ही विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष होंगे।

विश्व बैंक के बारे में:	विश्व बैंक बोर्ड के सदस्यों के बारे में:

- विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य विकासशील देशों में गरीबी को कम करना और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- इसकी स्थापना 1944 में की गई थे जिसका मुख्यालय वाशिंगटन, डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका में है।
- विश्व बैंक दो संस्थाओं से मिलकर बना है:
  - पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD) और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA)।
  - IBRD मध्यम और निम्न-आय वाले योग्य देशों को ऋण और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
  - जबकि आईडीए दुनिया के सबसे गरीब देशों को अनुदान और कम ब्याज पर ऋण प्रदान करता है।

- विश्व बैंक का एक कार्यकारी निदेशक मंडल होता है जो संगठन के प्रबंधन और दिशा की देखरेख करता है।
- बोर्ड में 25 सदस्य हैं जो बैंक के 189 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- प्रत्येक सदस्य देश बोर्ड में एक प्रतिनिधि नियुक्त करता है, जो आम तौर पर एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी या अर्थशास्त्री हो और जिसे विकास के मुद्दों में विशेषज्ञता प्राप्त होती है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका (जो विश्व बैंक में सबसे बड़ा शेयरधारक है) बैंक के अध्यक्ष की नियुक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करता है।
- बोर्ड एक-देश-एक-वोट प्रणाली पर काम करता है, जिसका अर्थ है कि निर्णय साधारण बहुमत के वोटों के आधार पर किए जाते हैं।
- हालांकि, प्रमुख निर्णय जैसे कि नई नीतियों की स्वीकृति या नए राष्ट्रपति के चयन के लिए समर्थन की उच्च सीमा की आवश्यकता होती है।

स्मार्ट सिटी मिशन

सन्दर्भ:

- हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपने स्मार्ट सिटीज मिशन की समय सीमा को जून 2023 बढ़ाकर जून 2024 कर दिया।

मुख्य विशेषताएं:

- इसे सभी 100 स्मार्ट शहरों को न केवल अपनी परियोजनाओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए, बल्कि मिशन से मिली सीख का दस्तावेजीकरण और प्रसार भी करने के लिए

विशेषताएँ :

- इसके रणनीतिक घटकों में 'क्षेत्र आधारित विकास', जिसमें शहर में सुधार (रेट्रोफिटिंग), शहर का नवीनीकरण (पुनर्विकास) और शहर का विस्तार (ग्रीनफ़ील्ड विकास) शामिल है, साथ ही एक पैन-

बढ़ाया गया।

- 100 में से 50 शहरों ने 75% परियोजनाओं को पूरा कर लिया है और जून तक शेष कार्यों को पूरा करने में सक्षम होंगे।

स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में

- स्मार्ट सिटीज मिशन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है जिसे 25 जून, 2015 को लॉन्च किया गया था।
- योजना का प्रकार- केंद्र प्रायोजित योजना
- देश भर के शहरों को नगरपालिका सेवाओं में सुधार करने और उनके अधिकार क्षेत्र को अधिक योग्य बनाने के लिए इन परियोजनाओं को प्रस्तावित किया गया।
- जनवरी 2016 और जून 2018 के बीच (जब अंततः शिलांग को चुना गया था), मंत्रालय ने पांच दौर में मिशन के लिए 100 शहरों का चयन किया।
- इन परियोजनाओं को शहर के चयन के पांच साल के भीतर पूरा किया जाना था, लेकिन 2021 में मंत्रालय ने सभी शहरों के लिए समय सीमा को बदलकर जून 2023 कर दिया, जो पहले केवल शिलांग के लिए समय सीमा थी।

सिटी पहल जिसमें शहर के बड़े हिस्सों को कवर करने के लिए 'स्मार्ट समाधान' लागू किए जाते हैं।

- योजना के मुख्य फोकस क्षेत्रों में वॉकवे, पैदल यात्री क्रॉसिंग, साइकिलिंग ट्रैक, कुशल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, एकीकृत यातायात प्रबंधन और मूल्यांकन शामिल हैं।
- यह योजना शहरी विकास को ट्रैक करने के लिए विभिन्न सूचकांकों का भी मूल्यांकन करती है जैसे कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, सिटी जीडीपी फ्रेमवर्क, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क आदि।

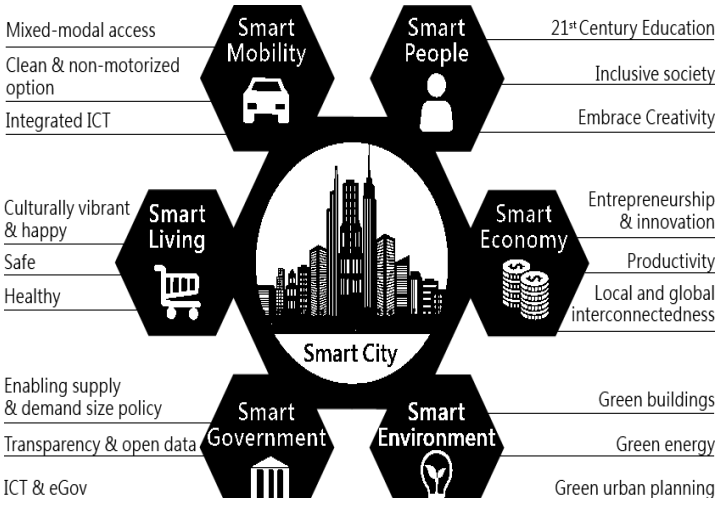

संक्षिप्तसुर्खियां

पोषण भी, पढाई भी

सन्दर्भ:

- आंगनवाड़ी केंद्रों को नए सिरे से पुनर्कल्पित और पुनर्गठन किया जायेगा जिसमें न केवल बच्चों और माताओं के पोषण संबंधी पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए

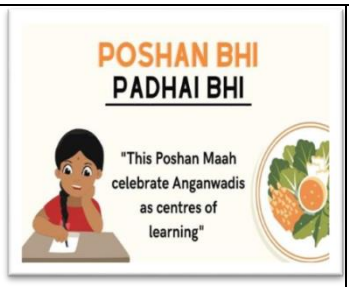

पुनर्गठित किया जाएगा बल्कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा।

मुख्य विशेषताएं:

- भारत सरकार छह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बचपन की देखभाल और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रही है।
- केंद्रों को प्री-स्कूलों के रूप में फिर से प्रोत्साहित किया जाएगा और विशेष रूप से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए प्रारंभिक शिक्षा पहुंच प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जाएगा।
- विभिन्न संस्थानों और स्वयंसेवकों को शामिल करते हुए एक टास्क फोर्स ने रीब्रांडिंग के लिए एक मिशन-मोड दृष्टिकोण की सिफारिश की है।
- टास्क फोर्स ने बुनियादी ढांचे में सुधार का भी सुझाव दिया है, जिसमें अंडे और दूध जैसे गुणवत्ता वाले पोषण पूरक शामिल हैं और तीन साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अन्य सुविधाओं की शुरूआत भी शामिल है।

भारत का घरेलू कोयला उत्पादन

सन्दर्भ:

- पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत का घरेलू कोयला उत्पादन 22% से अधिक बढ़ा है।

मुख्य विशेषताएं:

- देश के कुल कोयला उत्पादन की मात्रा में उछाल देखा गया जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 893.08 मिलियन टन है, इसमें वित्तीय वर्ष 2018-2019 में 728.72 मिलियन टन की तुलना में लगभग 22.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- सरकार की प्राथमिकता स्थानापन्न कोयले के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ाना है।

भारत में ओडीएफ प्लस जिला

सन्दर्भ:

- भारतीय राज्य केरल का वायनाड जिला भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला बन गया है।

मुख्य विशेषताएं:

- ओडीएफ का मतलब खुले में शौच मुक्त है। ओडीएफ कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा है, जिसे भारत सरकार ने 2014 में देश भर में स्वच्छता और स्वच्छता हासिल करने के लिए शुरू किया था। वायनाड जिले ने थ्री स्टार श्रेणी में ओडीएफ प्लस रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया, इसके बाद महाराष्ट्र में मनचेरियाल जिला और मध्य प्रदेश में अनुपुर जिले का स्थान रहा।
- वायनाड ने ओडीएफ रैंकिंग में एक परिपूर्ण 100 अंक प्राप्त किए, जबकि मनचेरियाल और अनुपुर ने क्रमशः 90.45 और 88.79 अंक प्राप्त किए।

आंतरिक शिकायत समिति

सन्दर्भ:

- भारतीय पहलवानों का 11 दिनों से नई दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी है।

मुख्य विशेषताएं:

- उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और साथी खिलाड़ियों से अपील की कि वे यौन उत्पीड़न की उनकी शिकायतों पर ध्यान दें।
- सरकार के एमसी मैरी कॉम की अध्यक्षता वाले पैनल ने इसे "प्रमुख खोज" के रूप में लाल झंडी दिखा दी, जहां कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन शोषण से बचाने वाले 2013 के यौन उत्पीड़न रोकथाम (पीओएसएच) अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से कोई आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) नहीं थी।

आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी):

- आंतरिक शिकायत समिति को PoSH अधिनियम के तहत किसी भी शिकायत के लिए सर्वप्रथम प्रभावी बनने के लिए विकसित किया गया था, जो महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कार्यस्थल वातावरण बनाने के लिए एक आवश्यक प्रमुख तत्व है।
- इसमें कम से कम चार सदस्य: उनमें से कम से कम आधी महिलाएं जिनमें से एक बाहरी सदस्य होगी, अधिमानतः एक गैर सरकारी संगठन या एक संघ से जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम करता है या एक वकील की तरह यौन उत्पीड़न

	से संबंधित मुद्दों से परिचित व्यक्ति होना चाहिए। • संघों को वार्षिक मान्यता प्रदान करने के लिए खेल मंत्रालय द्वारा स्थापित एक कार्यात्मक आंतरिक शिकायत समिति प्रमुख शर्तों में से एक है।
केंद्रीय प्रतिपक्ष (सीसीपी) 	**सन्दर्भ:** • यूरोपीय संघ के वित्तीय बाज़ार नियामक, यूरोपीय प्रतिभूति और बाज़ार प्राधिकरण (ESMA) ने यूरोपीय संघ (EU) के वित्तीय बाजार नियामक और पर्यवेक्षक ने 30 अप्रैल, 2023 से छह भारतीय केंद्रीय प्रतिपक्षों (CCP) की मान्यता रद्द कर दी। **मुख्य विशेषताएं:** • **मान्यता रद्द करने का कारण:** ESMA इन CCPs की निगरानी करना चाहता है। हालाँकि, भारतीय नियामक इसके पक्ष में नहीं हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इन संस्थाओं के पास मजबूत जोखिम प्रबंधन है और विदेशी नियामक को इनका निरीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। **केंद्रीय प्रतिपक्ष (Central Counterparties)** • केंद्रीय प्रतिपक्ष यूरोपीय बैंकों को समाशोधन सेवाएं तभी प्रदान कर सकता है जब इसे ईएसएमए द्वारा मान्यता प्राप्त हो। • सीसीपी एक बाजार लेनदेन में मध्यस्थ के रूप में दो मुख्य कार्य करते हैं- (1) समाशोधन और निपटान। (2) किसी व्यापार की शर्तों की गारंटी दें। • सीसीपी एक प्रणाली प्रदाता है, जो नए तरीके से निपटान के लिए स्वीकार किए गए लेन-देन में सिस्टम प्रतिभागियों के बीच हस्तक्षेप करता है, जिससे उनके लेन-देन के प्रभावी निपटान के उद्देश्य से प्रत्येक विक्रेता के लिए खरीदार और प्रत्येक खरीदार के लिए विक्रेता बन जाता है। CCP को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत भारत में संचालन के लिए RBI द्वारा अधिकृत किया गया है।

MCQ, Current Affairs, Daily Pre Pare